

ए स्थ्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा हरिद्वार के एक समारोह में उठा दिया है, आजकल कोई जिसका नाम भी नहीं लेता। न तो कोई राजनीतिक दल, न कोई सरकार और न ही कोई नेता 'अखंड भारत' की बात करता है। मोहनजी का कहना है कि अखंड भारत का यह स्वप्न अगले 15 साल में पूरा हो सकता है। ऐसा हो जाए तो क्या कहने? जो काम पिछले 75 साल में नहीं हुआ, वह सरकारों और नेताओं के भरोसे अगले 15 साल में कैसे हो

तब अखंड भारतः अब आर्यावर्त

सकता है? सबसे पहली बात तो यह है कि नेताओं को इस मुद्दे की समझ होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि उनमें इसे ठोस रूप देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मेरी विनाश राय है कि यह काम सरकारों से कहीं बेहतर वे गैर-सरकारी संस्थाएं कर सकती हैं, जो सर्वसमावेशी हों। 1945-50 के दिनों में युरू गोलवलकर ने अखंड भारत और डॉ. राममनोहर लोहिया ने भारत-पाक एका का

नारा दिया था। उस समय के लिए ये दोनों नारे ठीक थे लेकिन आज के दिन इन दोनों नारों के क्षेत्र को बहुत फैलाने की जरूरत है। ये दोनों नारे उस समय के अंग्रेज के भारत के बारे में थे लेकिन 50-55 साल पहले जब 15-20 पड़ौसी देशों में मुझे जाने और रहने को मिला तो मुझे लगा कि हमें महर्षि दयानंद के सपनों का आर्यवर्तूत खड़ा करना चाहिए। इस आर्यवर्ती की सीमाएं अराकान (स्थामार) से खुरासान (ईरान) और तिविष्टुप (तिब्बत) से मालदीव तक होनी चाहिए। इनमें मध्य एशिया के पांच गणतंत्रों और मोरिशस को जोड़ लें तो

यह 16 देशों का विशाल संगठन बन सकता है। बाद में इसमें थार्डलैंड और संयुक्त अरब अमीरात को भी जोड़ा जा सकता है। यह दक्षेस (सार्क) के आठ देशों से दुगुना है। 16 देशों के इस संगठन का नाम जन-दक्षेस है। दक्षेस सरकारों का संगठन है। पिछले 7-8 साल से यह ठप्प पड़ा हुआ है। जन-दक्षेस इन 16 देशों की जनता और सरकारों को भी जोड़ेगा। इन देशों को मिलाकर मेरा सपना है कि इसे यूरोपीय संघ से भी अधिक मजबूत और संपन्न संगठन बनाया जाए। हमारे इन राष्ट्रों में यूरोप से कहीं अधिक धन-संपदा गड़ी पड़ी हुई है। क्या

तेल, क्या गैस, क्या यूरोनियम, क्या सोना, क्या चांदी, क्या लोहा और क्या तांबा— सब कुछ हमारे इन देशों में इतना भरा हुआ पड़ा है कि अगले 5 साल में संपूर्ण दक्षिण और मध्य एशिया (आर्यावर्त्) के लोग यूरोपीय लोगों से भी अधिक मालदार बन सकते हैं और करोड़ों लोगों को नए रोजगार मिल सकते हैं। हमारे इन 16 देशों के मजहब, भाषाएं, वेशभूषाएं और खान-पान अलग-अलग हो सकते हैं लेकिन सांस्कृतिक दृष्टि से ये सब एक ही हैं, क्योंकि हजारों वर्षों से ये विशाल आर्यावर्त् के अभिन्न अंग रहे हैं।

संपादकीय

अमेरिका को झुकाया भारत ने

यू क्रेन के बारे में भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ा ही चला जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि हमारे रक्षा

और विदेश मंत्रियों की इस वांशिंगटन-यात्रा के दौरान कुछ न कुछ अप्रिय प्रसंग उठ खड़े होंगे लेकिन हमारे दोनों मंत्रियों ने अमेरिकी सरकार को भारत के पक्ष में झुका लिया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण वह संयुक्त विज्ञप्ति है, जिसमें यूक्रेन की दुर्दशा पर खुलकर बोला गया लेकिन रूस का नाम तक नहीं लिया गया। उसका विज्ञप्ति को आप ध्यान से पढ़ें तो आपको नहीं लगेगा कि यह भारत और अमेरिका की संयुक्त विज्ञप्ति है बल्कि यह भारत का एकल बयान है। भारत ने अमेरिका का अनुकरण करने की बजाय अमेरिका से भारत की हां में हां मिलवा ली। अमेरिका ने भी वे ही शब्द दोहराएं, जो यूक्रेन के बारे में भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहता रहा है। दोनों राष्ट्रों ने न तो रूस की भर्तसां की ओर न ही रूस पर प्रतिबंधों की मांग की। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी बिल्कंन ने यह मांग जरूर की कि दुनिया के सारे लोकतांत्रिक देशों को यूक्रेन के हमले की भर्तसां करनी चाहिए। भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन की जनता की दी जा रही भारतीय सहायता का भी जिक्र किया और रूस के साथ अपने पारंपरिक संबंधों का भी! बिल्कंन ने भारत-रूस संबंधों की गहराई को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार भी किया। भारत प्रशांत-क्षेत्र में अमेरिकी चौपुरों के साथ अपने संबंध घनिष्ठ बना रहा है। इस यात्रा के दौरान दोनों मंत्रियों ने अंतरिक्ष में सहयोग के नए आयाम खोले, अब अमेरिकी जहाजों की मरम्मत का टेका भी भारत को मिल गया है और अब भारत बहरीन में स्थित अमेरिकी सामुद्रिक कमांड का सदस्य भी बन गया है। इस यात्रा के दौरान अमेरिकी पक्ष ने भारत में मानव अधिकारों के हनन का सवाल भी उठाया। जयशंकर ने उसका भी करारा जवाब दिया। उन्होंने पूछा कि पहले बताइए कि आपके देश में ही मानव अधिकारों का क्या हाल है? अमेरिका के काले और अल्पसंख्यक लोग जिस दिरीता और असमानता को बर्दाशत करते रहते हैं, उसे जयशंकर ने बेहिचक रेखांकित कर दिया। जयशंकर का अभिप्राय था कि अमेरिका की नीति 'पर उपदेशकुशल बहुतेर' की नीति है। जहां तक रूसी एस-400 प्रक्षेपास्ट्रों की खरीद का सवाल है, उस विवादास्पद मुद्दे पर भी जयशंकर ने दो-टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह पांचवीं का अमेरिकी कानून है। इसकी चिंता अमेरिका करे कि वह किसी खरीददार पर पार्बद्धिया लगाएगा या नहीं? यह हमारी चिंता का विषय नहीं है। जयशंकर पहले अमेरिका में भारत के राजदूत रह चुके हैं। उन्हें उसकी विदेश नीति की बारीकियों का पता है।

य ह पहली बार नहीं है जब हिंदुओं का त्योहार

रामनवमी और मुसलमानों का रमज़ान साथ-साथ मनाया गया हो। यह भी पहली बार नहीं है जब साझे त्योहारों के मौसम में देश में सांप्रदायिकता फैलने का खतरा उमड़ा हो। पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक हवा में तंगिली के जहर के घुलने की गंध फैली है। कहीं रामनवमी के जुलूस पर हमला हुआ है, कहीं रमज़ान की नमाज़ में बाधा डालने की कोशिशें हुई हैं। और तो और, देश के सर्वत्रैष विश्वविद्यालयों में से एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रामनवमी के दिन सामिष भोजन के बनने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। इस तरह यी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं और अक्सर पूरा भारतीय समाज इसका खिमियाजा भुगतता रहा है। यह भी सही है कि समय के साथ अक्सर धाव भरते भी रहे हैं। लेकिन इस हकीकत से आंख नहीं चुरायी जा सकती कि धर्म के नाम पर भारतीय समाज को बांटने की कोशिशें लगातार होती रही हैं। कभी राजनीतिक स्वार्थों के लिए यह काम होता है और कभी बहुसंख्यकों के अधिकारों की दुहाई देकर। सवाल यह नहीं है कि पहला पत्थर किस ओर से फेंका गया या पहले ज्यादाती किसने की, सवाल यह है कि बहुधर्मी संस्कृति वाले भारत में जब-तब सांप्रदायिकता की आग क्यों जल उठती है? दशकों से (या सदियों से) साथ-साथ रहने वाले, साथ उठने-बैठने, खाने-पीने वाले, अचानक एक-दूसरे के दुश्मन कैसे बन जाते हैं? हमारा सर्विधान हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। हमारी सरकार किसी भी धर्म-विशेष से जुड़ी हुई नहीं है। हर नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपने विश्वास के अनुसार अपने धर्म का पालन करे। एक-दूसरे के धार्मिक व्यवहार में बाधा डालने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। सवाल तो यह उठता है कि बाधा डालने की आवश्यकता ही क्यों पड़े? और सवाल यह भी उठता है कि हर नागरिक को यह क्यों न लगे कि जितना मुझे अपना धर्म प्रिय है, उतना ही प्रिय दूसरे को उसका धर्म हो सकता है? हम तो हजारों साल से एक ईश्वर की बात कहते-मानते रहे हैं। फिर ईश्वर और अल्लाह में आस्था का



बंटवारा कैसे हो सकता है? हाल ही में रामनवमी के अवसर पर देश के अलग-अलग हिस्सों में सांप्रदायिक तनाव की स्थितियां पैदा हो गयी थीं। लेकिन, क्या पैदा हो गयी थीं कहना सही है? सच तो यह है कि ऐसी स्थितियां पैदा होती नहीं, पैदा की जाती हैं। हिंदुओं को क्यों लगता है कि रामनवमी का जुलूस जब किसी मस्जिद के सामने से गुज़रे तो नारे लगाना ज़रूरी है और मुसलमान यह क्यों समझते हैं कि अजान के लिए मस्जिद से लाउडस्पीकर की आवाज़ उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है? यह लाउडस्पीकर बाली बात भी अजीब ही है। पता नहीं कब से अजान की आवाज़ कुछ लोगों को नींद में बाधा लगाने लगी है? कइयों को तो यह ध्वनि-प्रदूषण का मामला लगाने लगा है। मज़े की बात यह है कि इस ध्वनि-प्रदूषण को रोकने के लिए 'ज्यादा ध्वनि-प्रदूषण' का सहारा लिया जा रहा है। कुछ दशक पहले महाराष्ट्र में शिवसेना ने 'महाआरती' आयोजित करने का अभियान छेड़ा था, अब राज ठाकरे की पार्टी

‘मनसे’ शिवसेना के दफ्तर के सामने माइक पर पाठ करती रही है! इसे क्या कहा जाये? राजनीतिक दांव-पेच? यह नादानी या दांव-पेच कुछ भी हो, देश की एकता और बंधुता के लिए खतरा है यह। आसेतु-हिमालय भारत एक बना रहे, इसके लिए ज़रूरी है धर्म को राजनीति का हथियार बनाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगे। बहुत सोच-समझकर हमने एक धर्म-निरपेक्ष भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला संविधान अपने लिए अंगीकृत किया था। पिचहतर साल से हम इस संविधान के अनुसार जीने की कोशिश करते रहे हैं। पच्चीस साल बाद हम धर्म-निरपेक्ष भारत की शताब्दी मनाएंगे। इस पच्चीस साल की अवधि को ‘अमृत-काल’ कहा जारहा है। यह अवधि हमारी धर्म-निरपेक्षता और गणतांत्रिक संविधान की जड़ों को मज़बूत करने वाली अवधि होनी चाहिए। जड़ों को मज़बूत करने का मतलब उन मूल्यों और आदर्शों के अनुरूप आचरण करना है जिन्हें आधार बनाकर हमने अपने भारत को बनाने के

अन्नदाता की बेकद्री: खरीद मंडियां सुविधा संप्लान बनायी जाए

ऐ से वक्त में जब कोरोना संकट के बाद रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते दुनिया में खाद्यान्न संकट की आहट महसूस की जा रही है, भारतीय किसानों की पसीने की महक देश को नया आत्मविश्वास दे रही है। निःसंदेह कोरोना की पहली लहर के बाद लगे सख्त लॉकडाउन के दौरान केवल कृषि क्षेत्र ने देश की जीड़ीपी को संबल दिया। वैशाखी की बवार किसानों में नई उमंग भर गई है वहाँ दूसरी ओर किसानों की अंतहीन समस्याएं खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। जहां तेज गर्मी की मार के चलते अनाज की गुणवत्ता में गिरावट आई है, वहाँ किसानों को मट्डियों में अनाज ले जाने से लेकर बेचने तक की प्रक्रिया में तमाम तरह की चुनावियों का सामना करना पड़ रहा है। विडंबन्य यह है कि सत्ताधीश ग्रामीण विकास, सड़कों व मट्डियों के रखरखाव तथा सुविधाओं के विस्तार के लिये आवंटित धन को अन्य मदों में खर्च कर देते हैं। इससे अन्नदाता की अंतहीन समस्याओं का समाधान संभव नहीं होता। इसका हालिया उदाहरण पंजाब का है, जहां अब तक ग्रामीण विकास फंड के दुरुपयोग के चलते केंद्र ग्रांट पर रोक लगाने की बात कर रहा था। उसके बाद वित्तीय संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने कानून लिया है जिसके लिए साप्तर्णी का



युक्तिसंगत समाधान निकाला। पंजाब सरकार ने केंद्र की शर्तों के अनुरूप पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) अध्यादेश-2022 को मंजूरी दे दी। इसके बाद राज्य सरकार रूरल डेवेलपमेंट फंड यानी आरडीएफ का पैसा केवल ग्रामीण विकास पर खर्च करेगी जिससे 1100 करोड़ रुपये की इस ग्रांट के पंजाब को मिलने का रास्ता साफ हुआ। दरअसल, इस ग्रांट को लेकर पंजाब का केंद्र से टकराव चल रहा था क्योंकि पूर्ववर्ती बादल व अमरेंद्र सरकार पर अनुदान का इस्तेमाल ग्रामीण विकास के बजाय अन्य कार्यों में खर्च करने के आरोप लगे। अब पंजाब सरकार का गहरी है कि ग्रांट की धनायाशी प्रटियों त

खरीद केंद्रों की सड़कों के निर्माण, मरम्मत, पेयजल व्यवस्था व भंडारण आदि पर खर्च की जायेगी। वहीं हरियाणा के किसान भी गर्मी की बजह से कम पैदावार के संकट से ज़बू रहे हैं। उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है कि गेहूं की पैदावार औसत से कम हुई तो बीमा कंपनियां नुकसान की भरपाई करेंगी। दरअसल, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कृषि विशेषज्ञ प्रत्येक गांव में फसल की औसत पैदावार का निर्धारण करेंगे। असल में, जनवरी में बेमौसमी बारिश व मार्च माह के मध्य में अप्रत्याशित गर्मी से गेहूं की फसलों को नुकसान पहुंचा है। आशंका है कि रबी की दूसरी फसलों का उत्पादन भी अन्य वर्षों के मुकाबले कम रह सकता है। राज्यों में गेहूं की कटाई शुरू हो चुकी है। दस से पंद्रह फीसदी कम उत्पादन की बात कही जा रही है। वहीं किसानों को अधिक तापमान के चलते कई तरह की अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। हरियाणा के कई जिलों में खड़ी फसलों में आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। द्युलासाती गर्मी व तेज हवा आग को फैलाने की बजह बनती हैं वहीं पंजाब की मैंडियों में गेहूं की फसल एफसीआई द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं आने से स्वतंत्र पार्टियां त्वरित में मंडोन क्षय रही हैं।

हिंदी को राष्ट्रभाषा स्वीकार करने में आखिर दिक्कत क्या है?

ज भाषा हिंदी की देशव्यापी स्वीकार्यता के आग्रह को लेकर केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषाई सियासत के तालाब में जो पथर फेंका है, उसकी अपेक्षित प्रतिक्रियाएँ ही आ रही हैं। शाह के बयान को 'हिंदी के भारतीय भाषाओं पर अतिक्रमण', 'गैर हिंदी भाषी राज्यों पर हिंदी थोपने' और 'हिंदी हिंदू हिंदुस्तान' की भाजपा की राजनीति का देश के सीमांत तक विस्तार की साजिश के रूप में निरूपित किया जा रहा है। शाह ने हाल में संसदीय राजभाषा समिति की 37 वीं बैठक में कहा कि देश में हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषाओं के लिए। उन्होंने कहा कि यह हिंदी शब्दकोश के संस्थाधन करने का समय है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट का 70 फीसदी एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जा रहा है। उन्होंने 9वीं क्लास तक के बच्चों के लिए हिंदी के प्रारंभिक ज्ञान और हिंदी शिक्षण परीक्षाओं पर अधिक ध्यान की जरूरत पर भी जोर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात शाह ने यह कही कि आज राजभाषा (हिंदी) को देश की एकता का महत्वपूर्ण अंग बनाने का समय आ गया है। उन्होंने इस घण्टे तोलने वाले मर्जियों के लिए आपाम में सहायता

हैं, तो यह भारत की भाषा में होनी चाहिए। मोटे तौर पर शाही धरान में ऐसा कुछ नहीं था, जिसका विरोध किया जाए। फिर राजनीतिक कारणों से तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और असम आदि राज्यों से विरोध के स्वर उठने शुरू हुए। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमेया ने ट्वीट किया, एक कन्नड़ के रूप में, मैं गृहमंत्री अमित शाह की आधिकारिक भाषा और संचार के माध्यम पर टिप्पणी के लिए कड़ी निंदा करता हूं। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हम इसे कभी दोने देंगे। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ टीएमसी ने कहा कि हम का सम्पान करते हैं लेकिन हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। शिवसेना ने आरोप लगाया कि शाह का बयान क्षेत्रीय औंगों के मूल्य को कम करने का एजेंडा है। खुद को अखिल भारतीय पार्टी मानने वाली कांग्रेस ने बीजेपी पर 'सांस्कृतिक कवाद' का आरोप लगाया है। उधर राष्ट्रीय छवि बनाने के लिए और राजनीति में उत्तरने का साहस न कर पाने वाले तमिल नेता राजनीकांत ने कहा कि पूरे भारत में एक ही भाषा की वास्तव मांग नहीं है।

संवेदनाओं के स्पंदन उकेरने का जुनून

चर्चित चेहरा



चंडीगढ़ के सेक्रेट हार्ट स्कूल की छात्रा रही हैं।
यहां से प्रारंभिक शिक्षा हासिल करने वाले
स्पंदिता ने निपट दिल्ली से फैशन डिजाइनिंग में
स्नातक की उपाधि हासिल की। बाद में वह
उच्च स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए
अमेरिका चली गई। भारतीय नारी के जीवन
की त्रासदियां स्पंदिता को विचलित करती रही हैं।
इसलिये उन्होंने महिला अधिकारों और
लैंगिक हिंसा पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

उन्होंने महसूस किया कि भारतीय राजनीतिक-सामाजिक परिदृश्य में एक आम महिला की त्रासदियों को लेकर संवेदनशील पहल नहीं हो पा रही है। उन्होंने देश में तमाम उन स्थानों का दौरा किया जहां परंपरागत कपड़ों की कलाकारी वाली कढ़ाई का काम होता था। उन्होंने एक विशेष प्रोजेक्ट के तहत इन महिलाओं की दिक्कतों का डॉक्यूमेंटेशन किया। उनके दुख-दर्द को करीब से महसूस किया। इन कामगारों का मनोबल बढ़ाने के लिये उनकी फोटुओं पर कढ़ाई करवायी, जिसके माध्यम से वे भारतीय श्रमशील महिलाओं की सामाजिक व मानसिक स्थितियों को उकरने में कामयाब रहीं। बाद में स्पॅदिता ने अपने फोटोग्राफी के जुनून को निखारने का मन बनाया। इसके लिये वर्ष 2019 में उन्होंने अमेरिका के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन से फोटोग्राफी में एमएफए की उपाधि हासिल की। उनके फोटोग्राफी के जुनून व कला-कौशल को संस्थान ने प्रतिष्ठा दी। इसके लिये उन्हें कई पुरस्कार भी मिले जिसमें डीन की मेरिट स्कॉलरशिप, फोटोग्राफी प्रोग्रामेटिक स्कॉलरशिप और ग्रेजुएट ट्रेवल ग्रांट अवार्ड जैसे सम्मान भी

है। फोटोग्राफी के इस जूनन ने तो खासी प्रतिष्ठा दिलायी। उन्हें एनटोग्राफी फैलोशिप (2021) और स्टोटोग्राफिक ग्रांट (2020) से भी किया गया। स्पृदिता को फोम पॉलर्ड (2020) के लिए नामांकित किया था। वे एपर्चर पोर्टफोलियो (2021) के लिए फाइनलिस्ट थीं। डेंसी प्रोग्राम, बुडस्टॉक, एनवाई में बुडस्टॉक आर्टिस्ट में डेंसी के लिए चुना गया था। न कला के बेमिस केंद्र (2021); बैकस्टर सेंट वर्कस्पेस रेजीडेंसी न्यू जर्सी में नारीवादी इनक्यूबेटर (2020) के लिये भी उनका चुनाव। मलिक के काम को आर्टी, आर्ट ज़ेफ़ीड, मुसी मैगज़ीन, हार्पर और एलीफेट मैगज़ीन में स्थान। उन्हें ब्रिटिश जर्नल ऑफ़ मोद्यूलर द्वारा 'वन्स टू वॉच 2020' में किया गया था। मलिक का एक 'वधु = द एम्ब्रायडर्ड ब्राइड', 2021 में बैकस्टर सेंट, एनवाई में किया गया।

 <h2>मेष</h2> <p>कार्यकुशलता एवं समृद्धि के योग फलप्रद हों, उके कार्य अवश्य बनेंगे।</p>	 <h2>वृष</h2> <p>कार्य तत्परता से लाभ होंगा, इष्ट मित्र सुखवर्धक हों तथा कार्य में अवश्य ध्यान दें।</p>	 <h2>मिथुन</h2> <p>व्यावसायिक अभियांत्रों में वृद्धि हो, कार्यकुशलता से संतोष, बिगड़े कार्य अवश्य बनेंगे।</p>	 <h2>कर्क</h2> <p>सोच-समझाकर शक्ति लगायें, अव्यवस्था, विभ्रम, विकार, कलेश, मन से परेशान हों।</p>
 <h2>सिंह</h2> <p>समय अनुकूलता हो, विशेष कार्य विथिगित रखें, लेन-देन में हानि होगी।</p>	 <h2>कन्या</h2> <p>मानसिक विभ्रम, किसी आरोप में फंस सकते हैं, सार्थकता से कार्य बनेंगे।</p>	 <h2>तुला</h2> <p>भारय का सितारा प्रबल हो, बिगड़े कार्य बनेंगे, कार्य संतोष अवश्य होगा।</p>	 <h2>वृश्चिक</h2> <p>कार्य-कुशलता से संतोष, योजनाएं फलीभूत होंगी, व्यावसाय में ध्यान दें।</p>
 <h2>धनु</h2> <p>सफलता के साधन जुटाएं, धन-लाभ होंगा, आशानुकूल सफलता का हर्ष होगा।</p>	 <h2>मकर</h2> <p>इष्ट मित्र सुखवर्धक हों, उत्री शरीर कष्ट, मित्र चिन्ता, ऋण से बचें।</p>	 <h2>कुंभ</h2> <p>इष्ट मित्र सहायक रहें, दैनिक कार्यगति में अनुकूलता आएंगी, ध्यान दें।</p>	 <h2>मीन</h2> <p>धन लाभ, सफलता का हर्ष, प्रभुत्व वृद्धि तथा सामाजिक कार्य बने जायेंगे।</p>

डॉ पीएल गौतमाचार्य

